on the basis of the recommendations and cost schedules prepared by the tariff commission. The price in any particular region depends upon recovery and duration. Those hon. Members who know the intricacies of it perhaps know that we have hardly any discretion in the matter once the formula is accepted.

SHRI S. KANDAPPAN: There cannot be any difference between Chittor in Andhra Pradesh and places like Ambum in Tamil Nadu a distance of hardly 30 or 40 miles.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Mysore is a separate zone; Andhra is a zone and Tamil Nadu is a separate zone. If the factories are in different States, the rates vary as recovery and duration vary from State to State. The price for Tamil Nadu is worked out on the basis of the schedule and the recommendations of the tariff commission.

MR. SPEAKER: This question has come before this House from time to time in some form or the other. I think I should go to the next question.

केन्द्रीय भाण्डागारों में स्टाक किए गये खाद्यान्नों का बीमा

+

*1173. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भाण्डागारों में स्टाक किये गये खाद्यान्नों का ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी से बीमा कराया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य बीमा कम्पनियां जिन दरों पर इन खाद्यान्नों का बीमा करने के लिये तैयार हैं, उनसे सरकार की कई लाख रुपये की बचत हो सकती है परन्तु कुछ अधिकारियों के कृत्यों के कारण यह बचत संभव नहीं है ;

(ग) क्या कुछ अन्य बीमा कम्पनियों ने इस बारे में सरकार को लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके अनुकूल प्रस्तावों पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Only one insurance company, *viz.* the Union Cooperative Insurance Society Limited, has written to the Government in this regard. But the Central Warehousing Corporation in the past received quotations from several insurance companies, including the Life Insurance Corporation of India.

(d) Does not arise, in view of the answer to part (b) above.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, सरकार ने बहुत सी इंश्योरेंस कम्पनियों से क्वोटेशन लिये थे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस कम्पनी का क्वोटेशन स्वीकार किया, जिसका क्वोटेशन सबसे कम था। क्या यह सच है कि अगर सरकार किसी को-आपरेटिव कैरेक्टर की कम्पनी से इंश्योरेंस कराती, तो विभाग को ज्यादा लाभ रहता और अधिक बचत होती ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In this matter, we are broadly governed by the general directive of Government. For instance, the Government has issued a directive that properties and goods under the direct and indirect control of Government should be insured either with the Indian Insurance Companies Association Pool or with the Life Insurance Corporation of India. As far as the Oriental Fire and General Insurance Company is concerned, it is 100 per cent a subsidiary of the LIC. So, it is almost a public sector organisation. Natural-

ly, while giving insurance, we have to take into consideration the general directive of the Government. Moreover, even the interests of the Corporation should also be looked into. In this particular case, I have looked into the facts and I find that the quotations from the Oriental Fire and General Insurance Company were very favourable as compared to the quotations given by others.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्वोटेशन्ज के फेवरेबल होने की बात नहीं है। मंत्री महोदय स्पष्ट तौर पर बतायें कि क्या इस कम्पनी के क्वोटेशन्ज सबसे कम थे।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: The point is, there are various aspects coming under insurance. Some of the insurance companies have a particular rate for tariff items as compared to the other non-tariff items. All these aspects have to be taken into consideration, and not a single item alone.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : गत वर्ष सरकार ने कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का इंश्योरेंस कराया और उसके लिए कितनी धनराशि इंश्योरेंस कम्पनी को पे की गई ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: About the precise amount, I will require notice. The goods which are stored in the warehouses of the Corporation are insured.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : आखिर मंत्री महोदय को यह बताने में क्या दिक्कत है कि सरकार ने कितनी धनराशि इस कम्पनी को इंश्योरेंस कमीशन के रूप में दी ? यह प्रश्न 21 दिन पहले दिया गया था। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पेसिफिक और रेलिवेंट है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: May I explain? It is a 100 per cent subsidiary of the LIC. I have explained that position. That is almost a Government concern, and no individual or any group of individuals stand to benefit, whatever amount is paid. As I said, if the hon. Member wants to have the information, I can give him, but the information is not with me now.

श्री शारदा नन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों ने इश्योरेंस करने के लिए आवेदन दिये थे, उनके नाम क्या हैं।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: May I explain it again, Sir? The Government have given a general directive to the public sector organisations that they must insure the goods either with the Life Insurance Corporation or with the Association that I have mentioned. If some private companies give some quotations we cannot give our insurance to them.

भूमिहीन बेरोजगार लोग

*1180. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जीवन-निर्वाह के कोई साधन नहीं हैं और जो बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि प्रयत्न करने के बावजूद उन्हें सरकारी कार्यालयों, उद्योगों तथा अन्य स्थानों में कोई रोजगार नहीं मिलता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन असहाय लोगों के लाभार्थ कोई ऐसे नियम बनायेगी जिनसे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जा सके ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार देश की मौजूदा बेरोजगारी (जिनमें भूमिहीन श्रमिकों की बेरोजगारी भी शामिल है) की